भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1336

03 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय : "नमो ड्रोन दीदी" कार्यक्रम के अंतर्गत महिला स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) का डेटा

#1336. श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) "नमो ड्रोन दीदी" कार्यक्रम के अंतर्गत ड्रोन प्रावधान के लिए चयनित महिला स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) की संख्या और चयन के लिए प्रयुक्त मानंदण्डों का राज्य-वार और आन्ध्र प्रदेश के लिए जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वितीय वर्ष 2024-25 के लिए "नमो ड्रोन दीदी" योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले स्व-सहायता समूहों की संख्या के लिए आन्ध्र प्रदेश के लिए राज्य स्तर पर और जिला-वार दोनों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और आन्ध्र प्रदेश राज्य के प्रत्येक जिले में इससे कितने लाभार्थी प्रभावित होने की संभावना है;

(ग) इस योजना के अंर्गत चयनित महिला स्व-सहायता समूहों की संख्या, ड्रोन किटों का आबंटन और दिए गए प्रशिक्षण का आन्ध्र प्रदेश राज्य का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) "नमो ड्रोन दीदी" योजना के कार्यान्वयन के लिए चयनित अग्रणी उर्वरक कंपनियों (एलएफसी) की सूची क्या है और आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में ड्रोनों की खरीद और वितरण, प्रशिक्षण और निगरानी में उनकी क्या भूमिका होगी?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क): सरकार ने 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए 1261 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में ' नमो ड्रोन दीदी ' को मंजूरी दी है। योजना के तहत आपूर्ति किए जाने वाले लक्ष्यित कुल 15,000 ड्रोन में से, प्रमुख उर्वरक कंपनियों (एलएफसी) ने अपने आंतरिक संसाधनों का उपयोग करके 2023-24 में पहले 500 ड्रोन खरीदे हैं और चयनित एसएचजी को वितरित किए हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश राज्य के एसएचजी को आपूर्ति किए गए 96 ड्रोन शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार के कृषि विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अधिक कीटनाशक खपत वाले मोनोक्रॉप क्षेत्रों वाले गांवों के समूह को इन 96 ड्रोन के वितरण के लिए चुना गया था। आंध्र प्रदेश राज्य में 2023-24 में एलएफसी द्वारा ड्रोन प्रदान किए गए स्वयं सहायता समूहों की जिलावार संख्या अनुबंध-I में दी गई है ।

(ख): राज्य के कृषि/कृषि अभियांत्रिकी विभाग, ग्रामीण विकास, दीनदयाल अन्त्योदय योजना का राज्य मिशन निदेशालय - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), राज्य सहकारिता विभाग, अग्रणी बैंक/राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राज्य के लिए नामित प्रमुख उर्वरक कंपनी (एलएफसी) के प्रतिनिधि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)/राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एसएयू)/ कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) के सदस्यों वाली राज्य स्तर की समिति ड्रोन उपयोग के लिए उपयुक्त समूहों के चयन, ड्रोन प्रदान करने के लिए चिन्हित किए गए समूहों में राज्यों में डीएवाई-एनआरएलएम के तहत प्रगतिशील महिला एसएचजी के चयन, ड्रोन पायलट और ड्रोन सहायक प्रशिक्षण के लिए महिला एसएचजी के सदस्यों के चयन, जिलेवार ड्रोन उपयोग के आकलन, मौजूदा गैप की पहचान, ड्रोन उपयोग की उपलब्धता और भविष्य की आवश्यकताओं, एलएफसी और कीटनाशक कंपनियों आदि के साथ समन्वय से चयनित महिला एसएचजी को व्यवसाय प्रदान करने/सुनिश्चित करने आदि के लिए जिम्मेदार हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पहले चरण में 3090 एसएचजी को ड्रोन वितरित करने का लक्ष्य है, जिसमें से 90 एसएचजी आंध्र प्रदेश राज्य से हैं। आंध्र प्रदेश सरकार के कृषि विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 2024-25 के पहले चरण में ड्रोन वितरण के लिए आवंटित एसएचजी की जिलेवार संख्या का विवरण अनुबंध- II में दिया गया है।

(ग): आंध्र प्रदेश राज्य में 2023-24 में ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए चुने गए एसएचजी के सदस्यों को 9-12 दिनों की अवधि का प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष 2024-25 के पहले चरण के दौरान उपलब्ध कराए जाने वाले ड्रोन को एक पैकेज के रूप में आपूर्ति किया जाना है, जिसमें एसएचजी के सदस्यों में से एक के लिए पंद्रह दिनों का प्रशिक्षण भी शामिल है। प्रशिक्षण में ड्रोन उड़ाना, ड्रोन नियमों के प्रावधानों को समझना, पोषक तत्व और कीटनाशक के उपयोग के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी), कृषि उद्देश्य के लिए ड्रोन उड़ाने का अभ्यास और ड्रोन की मामूली मरम्मत और रखरखाव शामिल है। बिजली के सामान, फिटिंग और मैकेनिकल कार्यों की मरम्मत करने की इच्छा रखने वाले चयनित एसएचजी के अन्य सदस्य/परिवार के सदस्य को राज्य स्तरीय समिति द्वारा चुना जाना है और उन्हें 5 दिनों के लिए ड्रोन सहायक के रूप में प्रशिक्षित किया जाना है।

(घ): इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको) को आंध्र प्रदेश राज्य के लिए प्रमुख उर्वरक कंपनी (एलएफसी) के रूप में नामित किया गया है। कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में इफको को राज्य स्तरीय समिति के साथ घनिष्ठ समन्वय में काम करना है। इफको प्रासंगिक सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ड्रोन की खरीद के लिए जिम्मेदार है । इसे ड्रोन के संचालन और रखरखाव के लिए ड्रोन आपूर्तिकर्ता कंपनियों और एसएचजी के क्लस्टर स्तरीय संघों (सीएलएफ) के बीच एक सेतु के रूप में भी काम करना है और ड्रोन द्वारा नैनो उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देना है। एलएफसी को एसएचजी/किसानों के प्रशिक्षण और जागरूकता को सुविधाजनक बनाना है।

अनुबंध- I

आंध्र प्रदेश राज्य में 2023-24 में एलएफसी द्वारा ड्रोन प्रदान किए गए स्वयं सहायता समूहों की जिला-वार संख्या

क्र. सं.	ज़िला	स्वयं सहायता समूहों की संख्या
1.	अल्लूरी सीतारामाराजू	1
2.	अनंतपुरम	3
3.	अन्नमय्या	5
4.	बापतला	6
5.	चित्तूर	5
6.	डॉ. बी.आर. कोनसीमा	1
7.	एलुरु	6
8.	काकीनाडा	4
9.	कृष्णा	6
10.	कुरनूल	8
11.	नांदयाल	9
12.	एनटीआर	3
13.	पलनाडु	4
14.	प्रकाशम	6
15.	एसपीएसआर नेल्लोर	4
16.	श्री सत्य साईं	1
17.	श्रीकाकुलम	11
18.	तिरुपति	2
19.	पश्चिमी गोदावरी	6
20.	वाईएसआर कडप्पा	5
	कुल	**96**

अनुबंध - II

आंध्र प्रदेश राज्य में 2024-25 के पहले चरण में ड्रोन वितरण के लिए आवंटित स्वयं सहायता समूहों की जिला-वार संख्या

क्र. सं.	ज़िला	स्वयं सहायता समूहों की संख्या
1.	श्रीकाकुलम	6
2.	पार्वतीपुरम मन्याम	15
3.	विजयनगरम	15
4.	काकीनाडा	20
5.	कृष्ण	9
6.	गुंटूर	16
7.	चित्तूर	9
	कुल	**90**

*****